

प्रेषक,

एस0के0मुटू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 20 मई, 2010

विषय:-एम0पी0सिंह फाउन्डेशन,पंजीकृत ट्रस्ट, दिल्ली को ग्राम कालेगांव, सहस्रधारा रोड, तहसील सदर, जिला देहरादून में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुल 10.533 है0 भूमि कय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-814/12 ए0-82 (2008-11)/बी0एल0आर0सी0, दिनांक-5.11.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, एम0पी0सिंह फाउन्डेशन,पंजीकृत ट्रस्ट, दिल्ली को ग्राम कालेगांव, सहस्रधारा रोड, तहसील सदर, जिला देहरादून में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कुल 10.533 है0 भूमि कय की अनुमति, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा-154 (2) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III)के अन्तर्गत, विद्यालयी शिक्षा विभाग/आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन की अनापत्ति/सहमति तथा आपके द्वारा संस्तुत खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा कय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (कक्षा 12 तक के विद्यालय की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था,उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

-2-

- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 8- संस्था द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग मात्र शैक्षणिक कार्यों हेतु ही किया जायेगा तथा इससे भिन्न कार्यों हेतु प्रस्तावित भूमि का उपयोग करने पर उक्त भूमि राज्य सरकार में स्वतः ही निहित कर ली जायेगी।
- 9- प्रश्नगत क्षेत्र देहरादून महायोजना 2025 से आच्छादित है एवं देहरादून महायोजना 2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन के अनुसार विकास प्राधिकरण की अनुमति द्वारा आवासीय परिक्षेत्र (आ0-1) में 12 मीटर चौड़े पहुँच मार्ग व न्यूनतम 35 मीटर चौड़े व 3.50 है० भूमि उपलब्ध होने पर विविध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की जायेगी।
- 10- प्रस्तावित स्थल पर, ईकाई द्वारा महायोजना में प्रस्तावित 12 मीटर चौड़े मार्गाधिकार भाग को सुनिश्चित रखा जायेगा।
- 11- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो। इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 12- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 13- योजना प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 14- सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 15- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस०के०मुट्टू)

प्रमुख सचिव।

पू०प०सं०-1059/समदिनांकित/2010

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

- 2- सचिव, शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन ।
- 3- सचिव, आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन ।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।
- 5- अधिकृत हस्ताक्षरी, एम0पी0सिंह फाउन्डेशन, पंजीकृत ट्रस्ट, पंजीकृत कार्यालय C-493, योजना विहार, दिल्ली-110092 ।
- 6- निदेशक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय ✓
- 7- प्रभारी मीडिया सेन्टर उत्तराखण्ड सचिवालय ।
- 8- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,



(संतोष बडोनी)

अनु सचिव ।